Tribunal, is rupees one lakh in case of death and total disability and ranges between Rs. 20,000 to Rs. 90,000 for injuries.

(c) The Government has decided to increase the amount of compensation payable for death and total disability to rupees two lakhs and between Rs. 16,000 to Rs. 1,80,000 for injuries with effect from 1-7-90 when the new Railway Act, 1989 will come into force.

Safety of High Rise Private Building

1092. SHRI SHIV PRATAP MISHRA:
SHRI SANTOSH BAGRODIA:
DR. YELAMANCHILI SIVAJI:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to reply to Starred Question 75 given in the Rajya Sabha on the 4th May, 1990 and state;

(a) the names of private building which do not have adequate fire fighting equipment; and

(b) the steps Government are taking to ensure the safety of high rise buildings in Delhi?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मध्य प्रदेश में डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

@1093. **श्री अजीत जोगी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य देश सरकार ने 75 सड़कों के निर्माण संबंधी कुछ प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे हैं, जिससे डाकू क्षेत्रों में आवागमन और परिवहन व्यवस्था में आसानी हो जाएगी और जिससे सरकार को डाकू समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी परियोजना रिपोर्ट में राज्य के दस्युग्रस्त क्षेत्रों में पहले चरण में 1 सड़कों और दूसरे चरण में 61 सड़कों के निर्माण के प्राक्कलन शामिल किए थे। इनमें से 14 सड़कों, जिनमें दूसरे चरण समूह की एक सड़क शामिल है, का अनुमोदन कर दिया गया है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना रिपोर्ट में बचे हुये कार्यों की 10 सड़कों के प्रशासनिक अनुमोदन के लिये राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। राज्य से पूर्ण सूचना के प्राप्त न होने के कारण समय पर प्रशासनिक अनुमोदन नहीं दिया जा सका। राज्य सरकार से, यदि आवश्यक हो, अनुमानों को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है तथा राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर प्रशासनिक अनुमोदन के लिये प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

प्रशासनिक अनुमोदन के लिये जब भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे, शेष सड़कों के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

Allotment of funds for construction of roads in tribal Areas

1094. SHRI MENTAV PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating allotment of funds for construction of roads in tribal areas; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) and (b) There is no proposal under consideration for allotment of funds for Construction of roads in tribal areas. However, a Centrally sponsored scheme for construction of roads in tribal areas with 100% Central assistance was earlier being implemented and administrative approvals were accorded upto 1987-88 Since Government of India has discontinued the scheme from 1987-88, funds were released upto 1989-90 for meeting only the committed liabilities on the already sanctioned works.

@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 938 16 मई, 1990 से स्थानांतरित ।